YOUNG INDIA > YOUNG PAPER

NBT

नवभारत टाइम्स

नई दिल्ली > शुक्रवार, 8 जनवरी 2016 > पौष 18 शक 1937 > पौष कृष्ण 13 विक्रम 2072 पेज 20* > मूल्य 4.50 रु. या 8.50

नर्सरी : सवालों के साथ स्कूल पहुंच रहे हैं पैरंट्स

Katyayani.Upreti@timesgroup.com

Photos : Sher Singh Saini

नई दिल्ली : नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के सरकार के आदेश के बाद पैरंट्स खुश तो हैं, मगर उलझन में भी हैं। उनका कहना है कि फैसला तो बढ़िया है, मगर एडमिशन प्रोसेस के बीच में अचानक यह ऑर्डर देना लापरवाही है। सरकार को फैसला दिसंबर में ही लेना चाहिए था, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा कई बरसों से चला रहा है और बेमतलब के क्राइटेरिया भी दिसंबर में ही वेबसाइट में नजर आने लगे थे।

उधर, स्कूलों का कहना था कि गुरुवार को क्राइटेरिया को लेकर पैरंट्स कई सवाल कर रहे थे, हालांकि फॉर्म की बिक्री पर असर नहीं पड़ा।

फैसले से खुशी, लेकिन क्राइटेरिया को लेकर उलझन बढ़ी

1 जनवरी से शुरू हुए नर्सरी एडमिशन प्रोसेस में बुधवार को ट्विस्ट आया, जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने करप्शन का हवाला देते हुए मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का ऐलान किया। 62 क्राइटेरिया को खत्म करने का आदेश भी निदेशालय की ओर से दिया गया। इस ऑर्डर के बाद प्राइवेट स्कूल परेशान हैं। स्कूलों की एक्शन कमिटी ने शुक्रवार को मीटिंग रखी है। एक्शन कमिटी, अनऐडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स के प्रेजिडेंट एस. के. भट्टाचार्य कहते हैं, मैनेजमेंट कोटा सालों से चलता आ रहा है, ऐसे में एडमिशन प्रोसेस के बीच में यह फैसला पैरंट्स और स्कूलों दोनों को कन्फ्यूजन ही देता है। अब हम हाई कोर्ट में ही इसे लेकर बात करेंगे।

नर्सरी के फॉर्म 22 जनवरी तक मिलने हैं। क्राइटेरिया को लेकर दिल्ली सरकार के आदेश के बाद गुरुवार को भी अच्छी-खासी तादाद में पैरंट्स स्कूल पहुंचे। वीएसपीके इंटरनैशनल स्कूल के चेयरमैन एसके गुप्ता के मुताबिक रोहिणी स्कूल में अब तक एक हजार फॉर्म सेल हुए हैं। वहीं जूनियर स्कूल पीतमपुरा में 300 फॉर्म बिक चुके हैं।

ईस्ट दिल्ली के स्नेह इंटरनैशनल स्कूल के चेयरमैन सुभाष ढींगरा कहते हैं, अब तक 740 ऑनलाइन-ऑफलाइन फॉर्म रजिस्टर हो चुके हैं और उसी हिसाब से आज भी फॉर्म बिके। मगर सरकार का यह फैसला अचरज भरा है क्योंकि गांगुली कमिटी के वक्त से ही 7 साल से मैनेजमेंट कोटा चल रहा था।

हमारे स्कूल में तो बच्चों को पॉइंट्स भी देना शुरू कर दिया गया था, ऐसे में स्टाफ की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। इसे लेकर 21 जनवरी को सरकार हाई कोर्ट में या फिर दिसंबर में भी बात कर सकती थी। माउंट आबू की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा कहती हैं, करीब 1200 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आज 125 फॉर्म बिके। हालांकि, क्राइटेरिया को लेकर अब हम भी परेशान हैं और पैरंट्स भी सवाल कर रहे हैं कि अब हम किस हिसाब से क्राइटेरिया बनाएंगे। एमएस पब्लिक स्कूल पीतमपुरा के डायरेक्टर सोमेश ऋषि पाठक कहते हैं, 800 फॉर्म लिए जा चुके हैं।

ऑल इंडिया पैरंट्स असोसिएशन के प्रेजिडेंट अशोक अग्रवाल कहते हैं, अचानक लिए गए इस फैसले से अब स्कूल और पैरंट्स दोनों ही सोच में पड़ गए हैं। अब स्कूल कोर्ट जाएंगे और ऐसे ही उलझन के हालत रहेंगे। प्रीत विहार के रहने वाले सूरज मिश्रा कहते हैं, मैं अपने बेटे के लिए तीन फॉर्म भर चुका हूं और अब अचानक हुए इस फैसले के बाद लग रहा है कि अब इंतजार ही ऑप्शन है।